नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 163
दि. 18.03.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

“इंसाफ के घर देर है, अंधेर नहीं”: ऊना की पीड़ा पर आठ साल बाद फैसला, सजा भी और सवाल भी

ऊना। न्याय की राह लंबी जरूर होती है, लेकिन जब फैसला आता है तो वह केवल एक केस का अंत नहीं, बल्कि समाज के आईने में झांकने का अवसर भी बन जाता है। गुजरात के ऊना में 2016 में दलित युवकों की सार्वजनिक पिटाई के मामले में विशेष अदालत के फैसले ने ठीक यही संदेश दिया है। करीब आठ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि 35 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। फैसले के साथ ही एक बार फिर यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या न्याय केवल सजा देने तक सीमित है या समाज में बदलाव की शुरुआत भी इसी से होती है।

यह मामला 11 जुलाई 2016 का है, जब मोटा समढियाला गांव में चार दलित युवकों को उस समय भीड़ ने बेरहमी से पीटा था, जब वे एक मृत गाय की खाल उतार रहे थे। यह काम उनके परिवारों का पारंपरिक पेशा था, लेकिन कथित ‘गौरक्षकों’ ने उन पर गोकशी का आरोप लगाकर उन्हें सरेआम अपमानित किया, अधनंगा किया और लाठियों से पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

वायरल वीडियो ने इस घटना को एक स्थानीय अपराध से उठाकर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए, दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुईं और सरकारों से लेकर न्यायपालिका तक पर सवाल उठे। यह घटना केवल हिंसा की नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और पूर्वाग्रह की भी प्रतीक बन गई थी।

अब जब वेरावल की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, तो उसमें सजा और राहत दोनों के पहलू सामने आए हैं। पांच दोषियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं—323, 324, 342 और 504—के तहत भी अलग-अलग अवधियों की सजा सुनाई गई है, हालांकि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही प्रत्येक दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दूसरी ओर, 35 आरोपियों को बरी किए जाने से एक नई बहस भी खड़ी हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर धाराओं—जैसे हत्या का प्रयास, डकैती और आपराधिक साजिश—को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यह फैसला इस बात की ओर इशारा करता है कि आपराधिक मामलों में भावनाओं के बजाय साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया ही निर्णायक होती है।

लेकिन यही तथ्य उन लोगों के लिए चिंता का विषय भी है, जो इस मामले को व्यापक सामाजिक अन्याय के रूप में देखते हैं।

इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान 200 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला कितना जटिल और संवेदनशील था। इतने लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया अपने आप में यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाया या नहीं। न्याय में देरी, भले ही अंततः फैसला आ जाए, पीड़ितों के लिए एक अलग तरह की पीड़ा लेकर आती है।

ऊना कांड ने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की उस सच्चाई को उजागर किया था, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह घटना केवल चार युवकों की पिटाई नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता का परिणाम थी, जो आज भी समाज के कुछ हिस्सों में गहराई से मौजूद है। इसने यह भी दिखाया कि किस तरह अफवाह, संदेह और भीड़ मानसिकता मिलकर कानून को अपने हाथ में लेने का खतरनाक रूप ले सकते हैं।

फैसले के बाद अब यह जरूरी हो जाता है कि इस घटना को केवल एक केस के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाए। यह चेतावनी है कि यदि समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत नहीं किया गया, तो ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। कानून अपना काम कर सकता है, लेकिन सामाजिक बदलाव केवल कानून के सहारे संभव नहीं है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। 2016 में इस घटना ने जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया था, उसी तरह अब यह फैसला भी नई बहस को जन्म दे सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इससे नीति निर्माण, कानून व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता के स्तर पर कोई ठोस बदलाव आता है या नहीं।

अंततः, ऊना कांड का यह फैसला एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है—जहां एक ओर दोषियों को सजा मिलने से न्याय की उम्मीद कायम रहती है, वहीं बड़ी संख्या में आरोपियों के बरी होने से कई सवाल भी अनुत्तरित रह जाते हैं। “इंसाफ के घर देर है, अंधेर नहीं” यह कहावत इस फैसले के साथ फिर दोहराई गई है, लेकिन यह भी सच है कि न्याय केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर स्तर पर दिखाई देना चाहिए। अब यह जिम्मेदारी केवल अदालत या प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है कि वह इस घटना से सीख ले और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे, जहां किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, पेशे या पहचान के आधार पर अपमानित या प्रताड़ित न किया जाए। तभी इस फैसले का वास्तविक अर्थ और महत्व समझ में आएगा।

मां होने का अधिकार अब बिना शर्त: गोद लेने वाली महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली। मातृत्व केवल जन्म देने का अनुभव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है—इस सिद्धांत को मजबूती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने देश की लाखों महिलाओं के अधिकारों को नई पहचान दी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाएं बच्चों को गोद लेती हैं, उन्हें भी वही मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए जो जैविक माताओं को मिलता है, चाहे बच्चा तीन महीने का हो या उससे बड़ा।

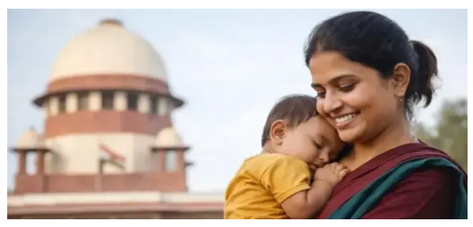

यह फैसला केवल एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि समाज में मातृत्व की परिभाषा को व्यापक और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले लागू नियमों के तहत, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत आते थे, केवल उन्हीं गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता था, जो तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को अपनाती थीं। इसका मतलब यह था कि यदि कोई महिला किसी बड़े बच्चे को गोद लेती है, तो उसे उस महत्वपूर्ण समय में बच्चे के साथ रहने का अधिकार नहीं मिलता था, जब उसे सबसे अधिक देखभाल, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब बच्चा किसी भी उम्र का हो, गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि मातृत्व अवकाश कोई विशेष सुविधा या दया नहीं, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है, जो हर मां को मिलना चाहिए।

इस फैसले की नींव संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। अदालत ने कहा कि पुराने नियम अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते थे। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। कोर्ट के अनुसार, जब एक महिला किसी बच्चे को गोद लेती है, तो वह उसी तरह उसकी मां बनती है, जैसे जैविक रूप से जन्म देने वाली महिला होती है। ऐसे में दोनों के अधिकारों में भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार बनाने के तरीके बदल रहे हैं और कानून को भी उसी के अनुरूप विकसित होना चाहिए। गोद लेना एक वैध और सम्मानजनक तरीका है, और इसे किसी भी तरह से कमतर नहीं आंका जा सकता। इस फैसले के जरिए न्यायपालिका ने यह संदेश दिया है कि समाज को पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर हर प्रकार के परिवार को समान सम्मान देना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू पितृत्व अवकाश से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह पिता के लिए भी एक स्पष्ट और व्यापक कानून बनाए, ताकि बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी केवल मां तक सीमित न रहे। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में यह आवश्यक है कि दोनों माता-पिता बच्चे के विकास में बराबर की भूमिका निभाएं। पितृत्व अवकाश न केवल पिता को अपने बच्चे के साथ समय बिताने का अवसर देगा, बल्कि यह परिवार के भीतर जिम्मेदारियों के संतुलन को भी मजबूत करेगा।

इस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक की वकील हंसानंदिनी नंदूरी की व्यक्तिगत लड़ाई से हुई थी। उन्होंने जब साढ़े चार और दो साल के बच्चों को गोद लिया, तो उनके नियोक्ता ने उन्हें पूर्ण मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया। यह केवल एक महिला की समस्या नहीं थी, बल्कि देशभर की उन हजारों महिलाओं की स्थिति थी, जो गोद लेने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाती थीं।

हंसानंदिनी नंदूरी ने इस अन्याय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया, और उनकी यह कानूनी लड़ाई आज एक ऐतिहासिक बदलाव में बदल गई। यह उदाहरण दिखाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष भी समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, यदि उन्हें सही दिशा और समर्थन मिले। इस फैसले का सामाजिक प्रभाव भी गहरा होगा। इससे गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अब महिलाओं को यह डर नहीं रहेगा कि उन्हें अपने करियर और मातृत्व के बीच कठिन चुनाव करना पड़ेगा। इसके अलावा, यह फैसला बच्चों के हित में भी है, क्योंकि उन्हें अपने नए परिवार के साथ शुरुआती समय में अधिक ध्यान और स्नेह मिल सकेगा, जो उनके भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। हालांकि, इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। कंपनियों को अपने एचआर नियमों को अपडेट करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को इस अधिकार का लाभ मिल सके।

‘नो शॉक’ पॉलिसी से सियासत और अर्थव्यवस्था दोनों को ऊर्जा, फडणवीस सरकार ने पांच साल तक बिजली दरें स्थिर रखने का किया ऐलान

मुंबई। महंगाई, ऊर्जा संकट और बढ़ती घरेलू जरूरतों के बीच महाराष्ट्र से आई एक बड़ी घोषणा ने आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक को राहत की सांस दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में अगले पांच वर्षों तक बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस फैसले को सरकार ने “नो शॉक” नीति का नाम दिया है, जिसका सीधा अर्थ है—बिजली बिल में कोई अप्रत्याशित झटका नहीं।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में बिजली दरों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में महाराष्ट्र सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह एक रणनीतिक निर्णय भी माना जा रहा है, जो राज्य की आर्थिक स्थिरता और निवेश आकर्षण को मजबूत कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मजबूत ऊर्जा प्रबंधन और दीर्घकालिक योजना का परिणाम है। सरकार का दावा है कि राज्य में बिजली उत्पादन, वितरण और प्रबंधन की स्थिति अब इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि दरों को पांच वर्षों तक स्थिर रखा जा सकता है। यह भरोसा उस समय और मजबूत होता है, जब राज्य की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी महावितरण ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल किया है, जो इसकी वित्तीय मजबूती का संकेत देता है।

इस नीति का सबसे बड़ा फायदा मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा, जो हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान रहते हैं। स्थिर दरों का मतलब है कि उन्हें अपने घरेलू बजट की योजना बनाने में आसानी होगी। किसानों के लिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई और कृषि कार्यों में बिजली की भूमिका बेहद अहम होती है। उद्योगों के लिए तो यह एक तरह का भरोसेमंद निवेश वातावरण तैयार करता है, जहां ऊर्जा लागत में अनिश्चितता नहीं रहती।

सरकार ने केवल दरों को स्थिर रखने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह पहल सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। दिन के समय बिजली उत्पादन अधिक होता है, खासकर सौर ऊर्जा के कारण, इसलिए सरकार चाहती है कि उपभोक्ता इसी समय अधिक बिजली का उपयोग करें।

यह कदम ऊर्जा प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें मांग और आपूर्ति के संतुलन को स्मार्ट तरीके से नियंत्रित किया जाता है। यदि अधिक लोग दिन में बिजली का उपयोग करेंगे, तो रात के समय पर लोड कम होगा, जिससे पूरे सिस्टम पर दबाव घटेगा और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

महाराष्ट्र का यह निर्णय केवल घरेलू और कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्य की डिजिटल और औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे डेटा सेंटर सेक्टर के लिए 4,500 मेगावॉट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। डेटा सेंटर आज के डिजिटल युग की रीढ़ बन चुके हैं, और उनकी सबसे बड़ी जरूरत है—स्थिर और सस्ती बिजली।

महाराष्ट्र पहले ही देश का एक प्रमुख औद्योगिक और आईटी हब है, और अब यह डेटा सेंटर उद्योग में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि कंपनियों को भरोसेमंद और किफायती बिजली मिलती है, तो वे यहां निवेश करने के लिए अधिक आकर्षित होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

उद्योगों की बढ़ती गतिविधियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में बिजली की खपत में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि केवल मांग का संकेत नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का भी प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली दरें अभी भी काफी प्रतिस्पर्धी हैं, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है।

हालांकि, इस पूरी योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। पांच वर्षों तक दरों को स्थिर रखना एक बड़ा वित्तीय दायित्व है, जिसके लिए सरकार को लगातार उत्पादन लागत, सब्सिडी और वितरण खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यदि ईंधन की कीमतों में वृद्धि होती है या मांग अपेक्षा से अधिक बढ़ती है, तो इस नीति को बनाए रखना कठिन हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का आत्मविश्वास यह संकेत देता है कि उसने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति सफल रहती है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।

सूरत से उठी वैश्विक कारोबार की नई लहर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को मिला संस्थागत सहारा

सूरत। भारत के टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में सूरत एक बार फिर केंद्र में आ गया है। 16 मार्च 2026 को यहां आयोजित एक भव्य रोड शो और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन मीटिंग ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले वर्षों में सूरत केवल देश का टेक्सटाइल हब ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निर्यात का एक मजबूत स्तंभ बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन टेक्सटाइल कमिटी ने सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित ‘टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर’ (TEFC) को लेकर उद्योग जगत को जागरूक करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।

सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों, निर्यातकों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। पूरे आयोजन में एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई—अब भारत का टेक्सटाइल उद्योग केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया जा रहा है।

इस प्रस्तावित ‘टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर’ को उद्योग के लिए एक ‘गेम चेंजर’ के रूप में देखा जा रहा है। खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए यह सेंटर एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। कार्तिकेय ढांढा ने अपने संबोधन में बताया कि छोटे और मध्यम उद्योगों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जटिल नियमों, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है। यही वजह है कि कई सक्षम निर्माता भी निर्यात के क्षेत्र में कदम नहीं रख पाते। TEFC इस खाई को पाटने का काम करेगा और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया। आर. चंद्रन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया कि यह सेंटर निर्यात से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं—चाहे वह लाइसेंसिंग हो, सर्टिफिकेशन हो या रेगुलेटरी कंप्लायंस—को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उद्यमियों के लिए प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी बन जाएगी। यह पहल खासतौर पर उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए फायदेमंद होगी, जो अब तक केवल घरेलू बाजार तक सीमित थे और अब सीधे एक्सपोर्टर बनने का सपना देख रहे हैं।

इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वृंदा देसाई ने सूरत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह शहर भारत के टेक्सटाइल इकोसिस्टम की धड़कन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो उसे निर्यात-केंद्रित सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना ही होगा। TEFC जैसे प्लेटफॉर्म न केवल तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे, बल्कि एक्सपोर्टर्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार की जटिलताओं को समझने और उनसे पार पाने में भी मदद करेंगे।

निखिल मद्रासी ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सूरत का योगदान भारत की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां के उद्योगों को यदि सही संस्थागत समर्थन मिले, तो वे वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं। इसी दिशा में TEFC एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कार्यक्रम में मौजूद शालीन तोशनीवाल ने मैनमेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में उभरते वैश्विक अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, और भारत के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है। यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो भारतीय टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ा सकता है।

वहीं अशोक जीरावाला ने इस पहल को उद्योग और सरकार के बीच की दूरी को कम करने वाला कदम बताया। उनके अनुसार, अक्सर नीति और जमीनी हकीकत के बीच एक अंतर रह जाता है, जिसे TEFC जैसे प्लेटफॉर्म दूर कर सकते हैं। इससे न केवल उद्योग की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा, बल्कि नीति निर्माण भी अधिक प्रभावी बन सकेगा।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित इंटरैक्टिव कंसल्टेशन सेशन इस पूरे आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ। इसमें स्थानीय उद्योगपतियों और निर्यातकों ने सीधे मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं, सुझाव और अनुभव साझा किए। इस संवाद ने यह स्पष्ट किया कि उद्योग जगत इस पहल को लेकर उत्साहित है, लेकिन साथ ही वह चाहता है कि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

इस मौके पर टेक्सटाइल कमिटी के डायरेक्टर जे.डी. बर्मन, पूर्व चैंबर अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, कोषाध्यक्ष मितेश मोदी, और पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती व हिमांशु बोडावाला सहित टेक्सटाइल जगत के कई दिग्गज मौजूद रहे। यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उद्योग और प्रशासन के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।

कार्यक्रम का समापन बी.के. शुक्ला के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नई शुरुआत का संकेत भी दे गया। सूरत से उठी यह पहल आने वाले समय में भारत के टेक्सटाइल निर्यात को नई दिशा दे सकती है।

कुल मिलाकर, ‘टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर’ केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक है, जो भारत को उत्पादन से आगे बढ़ाकर वैश्विक व्यापार में एक सशक्त खिलाड़ी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यदि यह पहल अपने उद्देश्यों में सफल होती है, तो सूरत न केवल भारत का, बल्कि दुनिया का एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्यात केंद्र बन सकता है।

संपादकीय

पंजाब-हरियाणा में मातृ स्वास्थ्य को गंभीरता से लें

हालांकि, पंजाब में पिछले दिनों सामने आए मातृ स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े कुछ हद तक उम्मीद जरूर जगाते हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्य में बच्चे को जन्म देने के दौरान मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जो निश्चित रूप से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माताओं की सेहत की सुरक्षा करने में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता में क्रमबद्ध सुधार का ही संकेत देती है। लेकिन, इस मामूली गिरावट के बावजूद एक गंभीर चिंता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि प्रगति अभी भी धीमी व असमान गति वाली है। दरअसल, मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों के रूप में मापी जाती है। जिसे व्यापक अर्थों में किसी भी समाज की स्वास्थ्य सेवा की क्षमता तथा समाज में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण सूचक भी माना जाता है। इस तरह मातृ मृत्यु दर में आई मामूली गिरावट भी प्रसव पूर्व गर्भवती स्त्री की देखभाल, संस्थागत स्तर पर प्रसव कराने और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की स्थिति में सुधार को ही दर्शाती है। इसके बावजूद अभी पंजाब में मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की काफी गुंजाइश है। विशेष रूप से तब जब कि कई जिलों में मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां जरूरी हो जाता है कि पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए। हालांकि, पहले इस दिशा में आशातीत प्रगति दर्ज की गई थी। लेकिन अब हरियाणा की मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर के नवीनतम मूल्यांकन चक्र में स्थिति लगभग अपरिवर्तित ही नजर आती है। निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखी जा रही यह स्थिरता सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में एक आम चुनौती को ही उजागर करती है। निर्विवाद रूप से प्रारंभिक स्तर पर किए गए सुधार अक्सर त्वरित लाभ देते हैं, लेकिन जरूरी है कि इस दिशा में प्रगति को अनवरत बनाया रखा जाए। निस्संदेह, इस प्रगति के लिये निरंतर गहन संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत होती है।

वास्तव में मातृ स्वास्थ्य रक्षा के लिये कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में केवल अस्पतालों और योजनाओं में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं होता है। बल्कि गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल, समय रहते रेफरल और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निरंतर निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, पंजाब में स्वास्थ्य संबंधी ऑडिट से पहले ही प्रणालीगत खामियों की ओर संकेत मिला है। जैसा कि निदान में देरी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी जटिलताओं का खराब प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कमजोर समन्वय का होना भी है। निस्संदेह, इन कमियों को दूर करने के लिये जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों से रेफरल नेटवर्क में यथाशीघ्र सुधार करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करने का संकल्प लिया है। यदि पंजाब और हरियाणा को इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उन्हें अपने प्रयासों में योजनाबद्ध ढंग से तेजी लानी होगी। इसमें दो राय नहीं कि मातृ मृत्यु दर महज चिकित्सा आंकड़े नहीं है। ये वो रोकी जा सकने वाली त्रासदी है, जो कई परिवारों और समुदायों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। निर्विवाद रूप से इस दिशा में जहां शासन की ओर से सजगता व सतर्कता की आवश्यकता होती है, वहीं चिकित्सा तंत्र से इस दिशा में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमारे समाज में आमतौर पर श्रमिक व वंचित तबका ही सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, जो महंगे अस्पतालों में अपनों का इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है। वे वंश वृद्धि और मातृ रक्षा की आस में सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। निस्संदेह, पर्याप्त सुविधा का अभाव व समय पर उपचार न मिलने से होने वाली हानि व्यवस्था पर भरोसे को कम ही करती है।

मस्तिष्क की सेहत पर मंडराता प्लास्टिक कणों का खतरा

> प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हवा, खाने और पानी के जरिए हर जगह फैल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक मानव मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्सों में जमा हो सकते हैं। वहीं रिसर्च में सामने आया कि मस्तिष्क में इनका स्तर लगातार बढ़ रहा है जो कुशाग्रता या दूसरे कार्यों पर असर डाल सकते हैं।

प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कण अथवा प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े हवा से लेकर पानी और खाने तक हर चीज में पाए गए हैं। अब डोनेट किए गए 52 मानव मस्तिष्कों पर हुए एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि ये माइक्रोप्लास्टिक कण मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्सों में जमा हो सकते हैं। शोधकर्ताओं को मस्तिष्क के हर सैंपल में पॉलीइथाइलीन और दूसरे पॉलिमर के निशान मिले और उन्होंने देखा कि हाल के सैंपल में पुराने सैंपल के मुकाबले इनकी मात्रा ज्यादा थी।

वैज्ञानिकों ने पाया कि 2024 में लिए गए सैंपल में प्लास्टिक की मात्रा 2016 में देखी गई मात्रा से अधिक थी,जिससे पता चलता है कि मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नई रिसर्च का नेतृत्व अमेरिका की न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी में टॉक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू कैम्पेन ने किया है। उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग में सावधानी बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा दुनियाभर में बढ़ता प्लास्टिक उत्पादन प्रदूषण की एक मुख्य वजह है।

विशेषज्ञों ने यह भी जांच की कि क्या कुछ खास परिस्थितियां इन वस्तुओं के जमाव को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने डिमेंशिया के मरीज़ों के एक ग्रुप को देखा जिनके मस्तिष्क में दूसरे सैंपल के मुकाबले तीन से पांच गुना ज्यादा प्लास्टिक के कण थे। वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए टुकड़ों के आकार देखकर हैरान गए। इन टुकड़ों में साफ-सुथरे गोलों के बजाय,कई दांतेदार, परत जैसी संरचनाएं थी। ऐसे ऊबड़-खाबड़ आकार वाले माइक्रोप्लास्टिक चिकने, गोल आकार वाले माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में कोशिकाओं के साथ अलग तरीके से क्रिया कर सकते हैं। पहले किए गए अनेक अध्ययनों में विभिन्न मानव अंगों,जैसे रक्त धमनियों, किडनी और प्लेसेंटा में प्लास्टिक के अपशिष्ट पाए गए हैं। प्रयोगशाला में चूहों के मॉडल पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि थोड़े समय के लिए सिंथेटिक पार्टिकल के संपर्क में आने से भी कई अंगों में सूजन हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन पार्टिकल की वजह

से खास बीमारियों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक का संपर्क लगभग हर जगह होता है। एक अन्य रिसर्च टीम ने देखा कि मस्तिष्क के ऑलफैक्ट्री बल्ब में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि इन टुकड़ों के नर्वस टिशू में घुसने के कई रास्ते हैं। ध्यान रहे कि ऑलफैक्ट्री बल्ब मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहां गंध की प्रोसेसिंग होती है। नई रिसर्च इस बात के प्रमाण देती है कि माइक्रोप्लास्टिक कण मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स में और भी गहराई तक जा सकते हैं। ये कण मस्तिष्क की कुशाग्रता या दूसरे कार्यों पर कैसे असर डाल सकते हैं, इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि डिमेंशिया वाले लोगों के दिमाग में अक्सर फिल्टरिंग सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, जिससे यह साफ नहीं होता कि प्लास्टिक की ज्यादा मात्रा ऐसी स्थितियों में योगदान करती है या यह मात्रा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि दिमाग उन्हें ठीक से साफ नहीं कर पाता।

जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क को याददाश्त में मामूली बदलाव और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में शुरुआती सेलुलर स्ट्रेस (कोशिकीय तनाव) के संकेतों से जोड़ा गया है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इंसानों पर हुए अध्ययन में यह साफ होने में सालों लग सकते हैं कि क्या माइक्रोप्लास्टिक कण सीधे स्नायु संबंधी दिक्कतें लाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जिस तरह प्लास्टिक का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह सूक्ष्म प्लास्टिक हवा, खाने और पानी के जरिए हर जगह फैल रहा है, उसे देखते हुए इस समस्या का कोई जल्दी समाधान नहीं निकल सकता।

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जब माइक्रोप्लास्टिक को दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों में जाने से रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान के बारे में कड़े नियम बनाना बहुत जरूरी है। कुछ अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि किस प्लास्टिक की छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित होने की सबसे ज्यादा संभावना है,इस पर हमें और डेटा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कणों के आकार और रासायनिक बनावट में अंतर मायने रखता है।

समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने बताया है कि समुद्रों में प्लास्टिक के कचरे के बारे में शुरुआती चेतावनियों को ज्यादातर नज़रअंदाज़ किया गया था, इसलिए इंसानी सेहत के लिए जरूरी उपायों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ के प्रोफेसर रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा है कि इन प्लास्टिक कणों को सेहत के नतीजों से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। थॉम्पसन ने ही सबसे पहले 'माइक्रोप्लास्टिक' शब्द का इस्तेमाल किया था। प्लास्टिक कणों का पता लगाने के नए तरीके वैज्ञानिकों को वह देखने में मदद कर रहे हैं जो कभी दिखाई नहीं देता था।

पिछले दस सालों में एडवांस्ड इमेजिंग टूल्स और रासायनिक विश्लेषण ज्यादा सटीक हो गए हैं, जिससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है। फिर भी, कई लोगों को चिंता है कि समस्या मौजूदा टेस्टों से ज्यादा बड़ी हो सकती है। अध्ययनों में उम्र,स्वास्थ्य की स्थिति और लाइफस्टाइल के फैक्टर्स का मुद्दा भी उठाया गया है, जो एक व्यक्ति के शरीर में दूसरे की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पर असर डाल सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक की इतनी विविधता होने से इसके हानिकारक प्रभाव का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पॉलीस्टाइनिन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन का आमतौर पर जिक्र किया जाता है, लेकिन दूसरे पॉलीमर भी मौजूद रहते हैं।

कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं,जबकि दूसरे रेशों में बदल जाते हैं जो टिशू में उलझ सकते हैं। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि माइक्रोप्लास्टिक से घबराने की कोई बात नहीं है लेकिन इसके बारे में जागरूकता रहनी चाहिए। ज्यादा जागरूकता से मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों, उपभोक्ता की पसंद और अवशिष्ट प्रबंधन में बदलाव आ सकते हैं। जैसे-जैसे ग्लोबल प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ेगा, भविष्य में इन प्लास्टिक कणों के अधिक स्तर को रोकने के लिए और कदम उठाने होंगे। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में भले ही कुछ सवाल बने रहें, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों,जानवरों और प्रयोगशाला में लगातार मिले नतीजे सावधानी बरतने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक दिमाग की कोशिकाओं या रक्त धमनियों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है,इसकी गहरी समझ से बचाव के रास्ते खुल सकते हैं।

प्रेरणा

भ्रम का संसार: जब सत्य खोकर जीवन एक स्वप्न बन गया

एक समय देवर्षि नारद अपने मन में एक सूक्ष्म अहंकार लिए हुए ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे भक्ति और ज्ञान के शिखर पर हैं और संसार की माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। वे जहां भी जाते, भगवान का नाम गाते और दूसरों को भी यही उपदेश देते कि मोह और माया से दूर रहो। लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं यह भावना घर कर चुकी थी कि वे स्वयं इस माया से परे हैं। यही विचार उन्हें एक दिन भगवान विष्णु के समक्ष ले गया।

नारद ने भगवान से कहा कि वे उनकी माया को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे कोई पिता अपने बालक की जिद को समझ रहा हो। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे उन्हें इसका अनुभव कराएंगे। कुछ समय बाद भगवान नारद को एक मरुभूमि से गुजारते हुए ले जा रहे थे। तपती धूप, दूर-दूर तक फैली रेत, और बीच-बीच में मरीचिका का आभास—वह स्थान स्वयं माया का प्रतीक लग रहा था।

चलते-चलते भगवान ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है और नारद से जल लाने को कहा। नारद तुरंत जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर ग्राम दिखाई दिया। वहां हरियाली थी, लोग प्रसन्न थे और जीवन सहजता से बह रहा था। नारद उस ग्राम में पहुंचे और एक घर के द्वार पर दस्तक दी। द्वार खोलने वाली युवती इतनी सुंदर थी कि एक क्षण के लिए नारद स्वयं को भूल गए। युवती की आंखों में एक अजीब आकर्षण था, जिसने नारद के मन को बांध लिया। उन्होंने जल मांगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला इतना लंबा खिंच गया कि वे अपने उद्देश्य को ही भूल गए। धीरे-धीरे वे उस परिवार का हिस्सा बन गए। समय के साथ उनका विवाह उसी युवती से हो गया और वे एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए।

अब नारद एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहे थे। खेतों में काम करना, परिवार का पालन करना, बच्चों की परवरिश करना—यही उनका संसार बन गया। उन्हें यह स्मरण भी नहीं रहा कि वे कौन थे और किस उद्देश्य से आए थे। वर्षों बीत गए, उनके बच्चे बड़े हुए, और जीवन अपनी गति से चलता रहा। वे अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन बिता रहे थे और यही उन्हें पूर्णता का अनुभव देता था।

लेकिन संसार की प्रकृति स्थिर नहीं होती। एक दिन उस ग्राम में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी ने धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लोग अपने-अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। नारद ने अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने बच्चों को कंधों पर उठाया, पत्नी का हाथ थामा और ऊंचाई की ओर भागने लगे।

लेकिन बाढ़ का वेग इतना अधिक था कि एक-एक करके उनके हाथ से सब कुछ छूटता गया। पहले एक बच्चा बह गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अंत में उनकी पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई। नारद अकेले खड़े रह गए, चारों ओर केवल पानी और विनाश था। वे रोने लगे, चिल्लाने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। उनका हृदय उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था।

उसी क्षण उन्होंने पीछे से एक परिचित स्वर सुना। "नारद, जल कहां है? तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो?" यह श्रीकृष्ण जैसा ही मधुर और गूंजता हुआ स्वर था, लेकिन वास्तव में वह भगवान विष्णु का ही था। नारद ने पीछे मुड़कर देखा और सब कुछ बदल गया। न बाढ़ थी, न ग्राम, न परिवार—केवल वही मरुभूमि थी और भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे।

नारद स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उन्होंने अभी-अभी अनुभव किया, वह क्या था। उनके लिए वह पूरा जीवन वास्तविक था—उनका प्रेम, उनका परिवार, उनका दुख—सब कुछ। लेकिन भगवान ने समझाया कि यह सब उनकी माया थी, एक ऐसा भ्रम जो इतना सशक्त होता है कि वह वास्तविकता का आभास देता है।

नारद के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि माया केवल बाहरी आकर्षण नहीं है, बल्कि यह मन के भीतर गहराई तक प्रवेश कर जाती है। यह मनुष्य को उसकी असली पहचान से दूर कर देती है और उसे एक ऐसे संसार में बांध देती है, जो अंततः अस्थायी और क्षणभंगुर है।

उन्होंने यह भी समझा कि माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह हमें "मैं" और "मेरा" के बंधन में बांध देती है। जब तक यह भावना बनी रहती है, तब तक मनुष्य दुख से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ भी हम "मेरा" मानते हैं, वह कभी न कभी हमसे छिन जाता है, और वही हमारे दुख का कारण बनता है।

इस अनुभव के बाद नारद का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। वे अब पहले की तरह केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने अनुभव से लोगों को समझाते थे कि जीवन में जो कुछ भी हम देखते हैं, वह एक गहरा भ्रम है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं।

यह कथा हमें यह सिखाती है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। हम अपने संबंधों, अपनी संपत्ति और अपनी इच्छाओं को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, जबकि यह सब क्षणिक है। जब हम इनसे जुड़ जाते हैं, तो उनका खोना हमें असहनीय पीड़ा देता है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि यह सब एक अस्थायी अनुभव है, तब हमारे भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। हम जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं, जहां हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तब हम सुख में भी संतुलित रहते हैं और दुख में भी विचलित नहीं होते। अंततः यही माया का रहस्य है—यह हमें बांधती भी है और सिखाती भी है। जो इसे समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। और जो इसमें उलझा रहता है, वह जन्म-जन्मांतर तक इसी चक्र में घूमता रहता है। यही जीवन का गूढ़ सत्य है, जिसे जानकर ही मनुष्य वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकता है।

शक्तिशाली गठबंधन NATO की कमजोरी हुई उजागर, युद्ध में America पड़ा अकेला, तमाशबीन बना Europe

अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़ा गया ईरान युद्ध अब वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला भूचाल बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि पश्चिमी दुनिया का अहम स्तंभ माने जाने वाले यूरोपीय देश इस पूरे संकट में लगभग दर्शक बने बैठे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों वह अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ इस युद्ध में उतरने से बच रहे हैं? देखा जाये तो फरवरी माह के अंत में शुरू हुए इस संघर्ष ने मध्य पूर्व को आग के गोले में बदल दिया है। लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि क्षेत्र में स्थिरता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। इसके बावजूद यूरोप ने साफ तौर पर दूरी बना रखी है और यही दूरी अब पूरी दुनिया के लिए नई पहेली बन गई है। देखा जाये तो यूरोप की इस दूरी का सबसे पहला कारण है कानूनी वैधता का संकट। यूरोप के कई बड़े देश मानते हैं कि इस युद्ध के लिए कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय मंजूरी नहीं है। बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के सीधे युद्ध में कूदना उनके लिए न केवल जोखिम भरा है, बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक साख पर भी सवाल खड़े कर सकता है। यही वजह है कि वह इस टकराव से खुद को दूर रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है रणनीतिक अस्पष्टता। अमेरिका इस युद्ध में आखिर हासिल क्या करना चाहता है, यह अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। क्या लक्ष्य केवल ईरान को कमजोर करना है, या वहां सत्ता परिवर्तन की योजना है, या फिर यह महज शक्ति प्रदर्शन है। जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक यूरोप अपने सैनिकों और संसाधनों को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। तीसरा और बेहद गंभीर कारण है ऊर्जा संकट का खतरा। ईरान की स्थिति ऐसी है कि वह वैश्विक तेल आपूर्ति को सीधे प्रभावित कर सकता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सबसे बड़ा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे यूरोपीय देश इस जोखिम को और बढ़ाना नहीं चाहते। उधर, अमेरिका लगातार अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहा है कि वह इस युद्ध में शामिल हों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन यूरोप की प्रतिक्रिया ठंडी और सतर्क है। कुछ देशों ने तो खुलकर इस युद्ध की आलोचना तक कर दी है। उन्होंने कहा है कि यह संघर्ष न केवल खतरनाक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी कमजोर करने वाला कदम है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह युद्ध सीमित नहीं रहेगा। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। आतंकवाद, शरणार्थियों की लहर और क्षेत्रीय अराजकता सीधे यूरोप के दरवाजे तक पहुंच सकती है। पिछली बार के अनुभवों ने उन्हें पहले ही सावधान कर दिया है, इसलिए इस बार वह बिना सोचे समझे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप संतुलित और दूरी बनाए रखने की नीति पर चल रहा है। यह अंतर साफ संकेत देता है कि अब वैश्विक राजनीति में पुराने समीकरण बदल रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी इस युद्ध के गंभीर असर दिखने लगे हैं। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव है और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी इस बात का संकेत हैं कि आम जनता इस संघर्ष से खुश नहीं है।

देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम के दूरगामी असर बेहद गंभीर हो सकते हैं। एक तो इससे पश्चिमी एकता कमजोर होती नजर आ रही है। अगर यूरोप और अमेरिका के बीच यह दूरी बढ़ती है, तो वैश्विक स्तर पर उनके गठबंधन की विश्वसनीयता को झटका लग सकता है। साथ ही इस युद्ध से ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। अगर तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है क्योंकि जब सहयोगी ही पूरी तरह साथ नहीं हैं, तो किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। साथ ही वैश्विक व्यवस्था में बदलाव भी तय नजर आ रहा है। देश अब पुराने गठबंधनों से हटकर अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहे हैं। यह संकेत है कि आने वाले समय में दुनिया और ज्यादा बंटी हुई नजर आ सकती है।

बहरहाल, यूरोप की खामोशी दरअसल उसकी मजबूरी और रणनीति दोनों का मिश्रण है। वह इस आग में कूदने से बच रहा है, लेकिन यह दूरी उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकती। अगर यह युद्ध और फैलता है, तो इसकी लपटें यूरोप तक जरूर पहुंचेंगी। यानी फिलहाल यूरोप भले ही तमाशबीन बना बैठा हो, लेकिन आने वाला समय उसे भी इस संकट के केंद्र में खींच सकता है। यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है।

अभियान

युगांत की वह घड़ी: जब श्रीकृष्ण के प्रस्थान के साथ समय ने बदला अपना स्वरूप

जब श्रीकृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपनी लीला पूर्ण करने का निर्णय लिया, तब केवल एक अवतार का अंत नहीं हो रहा था, बल्कि समय स्वयं एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। वह क्षण केवल इतिहास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय परिवर्तन का प्रतीक था। कहते हैं कि वह दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का था, जब आकाश में सूर्य की पहली किरणें एक नए युग के स्वागत में प्रकट हो रही थीं, और उसी समय द्वापर युग अपने अंतिम श्वास ले रहा था।

समुद्र तट पर बसी दिव्य नगरी द्वारका, जो कभी वैभव, नीति और धर्म का केंद्र थी, धीरे-धीरे लहरों में समा रही थी। ऊंची-ऊंची लहरें मानो समय के हाथ बनकर उस महान सभ्यता को अपने भीतर समेट रही थीं। यह दृश्य केवल एक नगर के डूबने का नहीं था, बल्कि उस युग की समाप्ति का संकेत था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संतुलन अभी भी विद्यमान था। जैसे ही द्वारका लहरों में विलीन हुई, वैसे ही मानव सभ्यता एक नए युग—कलियुग—की दहलीज पर खड़ी हो गई।

इस परिवर्तन के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा भी छिपी है। बलराम, जो श्रीकृष्ण के बड़े भाई थे, पहले ही संसार से विरक्त होकर वन में चले गए थे। उन्होंने योग की उच्च अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए, जैसे कोई साधक अपने शरीर को केवल एक वस्त्र की तरह छोड़ देता है। यह संकेत था कि अब श्रीकृष्ण के पृथ्वी पर रहने का समय भी समाप्त होने वाला है। श्रीकृष्ण ने जब देखा कि उनके वंशज, यादव, आपसी संघर्ष में नष्ट हो चुके हैं, तब उन्होंने समझ लिया कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे वन में चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में लेट गए। उस समय उनका मन पूर्णतः शांत था, जैसे समुद्र की गहराई में स्थिर जल होता है। उसी समय एक बहेलिया, जिसका नाम जरा बताया जाता है, वहां से गुजर रहा था। उसने दूर से श्रीकृष्ण के पद को किसी हिरण का मुख समझ लिया और अनजाने में बाण चला दिया। वह बाण आकर श्रीकृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही बाण लगा, उनकी योगनिद्रा भंग हुई, और उन्होंने उस बहेलिए को भय से कांपते हुए देखा। बहेलिया अपने अपराध से व्याकुल था, लेकिन श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित है, और उसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।

उस क्षण में श्रीकृष्ण ने अपनी समस्त इंद्रियों को समेट लिया और अपने दिव्य स्वरूप में ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी का त्याग किया, समय ने अपना रूप बदल लिया। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलियुग का प्रारंभ हुआ। यह परिवर्तन केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि अब मानवता एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है, जहां धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार होगा।

कहते हैं कि उस समय से अब तक लगभग 5127 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में मानव समाज ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। कलियुग की विशेषता यह है कि इसमें सत्य धीरे-धीरे क्षीण होता जाता है, और मनुष्य का मन भौतिकता में अधिक उलझता चला जाता है। फिर भी, इस युग की एक विशेषता यह भी है कि इसमें भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी माना गया है।

पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की आयु अत्यंत विशाल है। एक ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, करोड़ों वर्षों का होता है। उसमें हजारों चतुर्युगियां आती हैं, जिनमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग का चक्र चलता रहता है। यह चक्र केवल समय का मापन नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास और पतन का प्रतीक भी है। जब युग बदलता है, तो केवल समय नहीं बदलता, बल्कि प्रकृति, समाज और मानव के विचार भी बदलते हैं। इसी कारण हमारे ऋषियों ने समय की गणना को केवल गणित तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़ा। चैत्र मास की प्रतिपदा को नववर्ष का प्रारंभ मानना इसी विचार का परिणाम है। यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं को नए रूप में ढालती है, पेड़-पौधे नए पत्तों से सजते हैं, और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।

इसी समय नवरात्र का भी आयोजन होता है, जिसमें शक्ति की उपासना की जाती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बैठाता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत कर सकता है।

समय के साथ भारतीय संस्कृति ने अनेक आक्रमणों और परिवर्तनों का सामना किया, लेकिन इसकी मूल भावना कभी समाप्त नहीं हुई। लगभग दो हजार वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर एक नए युग की शुरुआत की, जिसे विक्रमी संवत के नाम से जाना गया। यह केवल एक कालगणना नहीं, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक था, जो भारतीय सभ्यता की पहचान है।

इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इसी दिन हस्तिनापुर का शासन संभाला था, जो धर्म और न्याय के आदर्शों पर आधारित था। बाद में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी इसी दिन आर्य समाज की स्थापना कर समाज में वैदिक विचारों को पुनः जागृत करने का प्रयास किया।

इस प्रकार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां इतिहास, धर्म, प्रकृति और समय एक साथ मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, जिसमें परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है।

आज जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अपने मूल से दूर होते जा रहे हैं, तब इस प्रकार की कथाएं हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर देती हैं। वे हमें यह समझने में सहायता करती हैं कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन आत्मा हैं, जो समय के इस विशाल चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है।

श्रीकृष्ण का महाप्रस्थान हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। द्वापर का अंत हुआ, तो कलियुग का आरंभ हुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब एक अध्याय समाप्त होता है, तो एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। यदि हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें, तो जीवन का हर मोड़ हमें एक नई दिशा दे सकता है।

अंततः यह कथा हमें यह संदेश देती है कि समय के इस अनंत प्रवाह में हमें अपने मूल्यों और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यही वे आधार हैं, जो हमें स्थिरता और दिशा प्रदान करते हैं। जब हम अपने अतीत को समझते हैं, तब ही हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

गैस कनेक्शन पर सख्ती: अब एक ही विकल्प चुनना होगा, डुअल कनेक्शन पर रोक से मचा हड़कंप

राजकोट। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव लागू हुआ है, जिससे ऊर्जा उपयोग के तरीके, सरकारी नियंत्रण और बाजार की पारदर्शिता—तीनों को एक साथ प्रभावित करना शुरू कर दिया है। गुजरात में लागू नई गाइडलाइंस के तहत अब उपभोक्ता LPG और PNG में से केवल एक ही गैस कनेक्शन रख सकेंगे। दोनों कनेक्शन एक साथ रखने की अनुमति समाप्त कर दी गई है। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि गैस वितरण प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने के लिए, राजकोट जिला प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाई है। जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में GSPC सहित विभिन्न गैस वितरण कंपनियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जिला सप्लाई ऑफिसर अजय झापड़ा ने विस्तार से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी "लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026" को राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब किसी भी उपभोक्ता को दोहरे गैस कनेक्शन रखने की छूट नहीं होगी। जिन लोगों के पास पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है, वे अब नया LPG कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन पहले से हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से LPG कनेक्शन वापस करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों से LPG सिलेंडर की रिफिल नहीं दी जाएगी। इस प्रावधान ने उपभोक्ताओं के सामने स्पष्ट विकल्प रख दिया है—या तो पाइप्ड गैस चुनें या सिलेंडर गैस, दोनों नहीं।

इस फैसले के पीछे सरकार की सोच बहुआयामी है। सबसे पहले, यह कदम गैस की अनावश्यक जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। लंबे समय से यह

देखा जा रहा था कि कई उपभोक्ता सुरक्षा या सुविधा के नाम पर दोनों प्रकार के कनेक्शन लेकर गैस का अतिरिक्त भंडारण करते हैं। इससे वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पाती थी। विशेष रूप से त्योहारों या आपूर्ति में कमी के समय यह समस्या और गंभीर हो जाती थी।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण गैस की ब्लैकमार्केटिंग पर रोक लगाना है। प्रशासन के अनुसार, कई मामलों में घरेलू LPG सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। हाल ही में राजकोट जिले में होटल, रेस्टोरेंट और हाईवे ढाबों पर की गई औचक जांच में करीब 150 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि गैस का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका था, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था।

नई गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने निगरानी तंत्र को भी काफी मजबूत किया है। प्रत्येक गैस एजेंसी और गोदाम पर एक राजस्व कर्मचारी और एक पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि गैस वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा जिला सप्लाई विभाग लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संपर्क में है, ताकि गैस की उपलब्धता बनी रहे और किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी पैदा न हो।

इस नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता है। जब एक उपभोक्ता के पास केवल एक ही गैस कनेक्शन होगा, तो वितरण प्रणाली को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सब्सिडी का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति दोहरे लाभ का दुरुपयोग न कर सके। यह कदम डिजिटल रिकॉर्ड और आधार-आधारित सत्यापन प्रणाली के साथ मिलकर गैस वितरण को और अधिक व्यवस्थित बना सकता है।

हालांकि, इस फैसले के कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। कई उपभोक्ता, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, सुविधा के लिए, PNG और बैकअप के रूप में LPG दोनों का उपयोग करते थे। अब उन्हें एक विकल्प छोड़ना होगा, जो उनके दैनिक जीवन में बदलाव ला सकता है। वहीं ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां PNG की उपलब्धता सीमित है, वहां यह निर्णय अपेक्षाकृत कम प्रभावी होगा, क्योंकि अधिकांश लोग पहले से ही LPG पर निर्भर हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह गैस वितरण प्रणाली में एक बड़ा सुधार ला सकती है। इससे न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि PNG को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। साथ ही, यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नई गाइडलाइंस का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय किसी को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को समान और सुचारू रूप से गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह नीति कितनी सफल होती है और क्या यह देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह लागू की जाती है। फिलहाल, राजकोट इस बदलाव का केंद्र बन चुका है, जहां से गैस वितरण व्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यह बदलाव केवल नियमों का नहीं, बल्कि उपभोक्ता व्यवहार और प्रशासनिक दृष्टिकोण दोनों का संकेत है, जो आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है।

सूरत के सहकारी बैंकों पर आरबीआई का जुर्माना और भ्रष्टाचार की शिकायतें - तत्काल सख्त कार्रवाई आवश्यक

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आम तौर पर सहकारी बैंकों की शुरुआत सदस्यों को आसानी से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। यही बात सार्वजनिक रूप से चर्चा में है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सहकारी बैंकों को सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करना होता है। लेकिन शायद ही कोई बैंक इनका पालन करता है। और सहकारी बैंकों में भी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन व्याप्त है। आरबीआई द्वारा ऐसे बैंकों पर लगाए गए जुर्माने से पता चलता है कि जुर्माना जितना अधिक होता है, घोटाले उतने ही बड़े होते हैं। सहकारी बैंकों के प्रशासकों की प्रशासनिक विफलताओं के कारण बैंकों पर इतने भारी जुर्माने लगाए गए हैं। अधिकांश प्रशासक अपने अहंकार और शीर्ष पर पहुंचने के भ्रम में जी रहे हैं।

इसी कारण वे बैंकों को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाते हैं और बैंक की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। आम सदस्यों को बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के पापों का खामियाजा भुगतना पड़ता है।

जिन बैंकों पर वित्तीय दंड लगाया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है। हालांकि, बैंक निदेशकों, जिला रजिस्ट्रार और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया है। सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (जनवरी 2026): पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और ऋण/अग्रिम प्रबंधन नियमों का अनुपालन न करने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मांडवी नागरिक सहकारी बैंक, सूरत (जुलाई 2025): स्वीकृत ऋणों के संबंध में निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने में चूक, विशेष रूप से ऋणों के प्रबंधन के संबंध में, के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (सितंबर 2025): इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित ग्राहक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक (सितंबर 2023): परिपक्व जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करने और ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की तत्काल रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में गुजरात के सूरत में स्थित कई सहकारी बैंकों पर नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। मुख्य कार्यवाही में सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 18.30 लाख रुपये का जुर्माना, प्राइम को-ऑपरेटिव बैंक पर 15 लाख रुपये का जुर्माना और सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर 14 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है, मुख्य रूप से सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग, ब्याज भुगतान और ऋण नियमों से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए। सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सितंबर 2025): बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े ऋणों की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर 18.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

प्राइम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (अगस्त 2025): साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का अनुपालन न करने और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए सुविधाएं प्रदान करने में विफलता या देरी के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कुप्रबंधन के लिए:-

सूरत के जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मांडवी नागरिक सहकारी बैंक सूरत, पंचशील मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत, सूरत राष्ट्रीय सहकारी बैंक, सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जबकि बैंकों के बोर्डों को तत्काल भंग किया जाना चाहिए।

अहमदाबाद रेल मंडल में 'कवच 4.0' का तेजी से विस्तार: सुरक्षित सफर की ओर बढ़ते कदम; अहमदाबाद–पालनपुर, सामाख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर कवच इंस्टालेशन कार्य प्रगति पर

जीएनएस)। कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआइएल-4) के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है, लोको पायलट के ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। यह भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कवच भारतीय रेल द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इसका उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना, सिग्नल उल्लंघन (SPAD) से बचाव करना तथा सुरक्षित और नियंत्रित संचालन सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में RFID (Radio Frequency Identification) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत ट्रैक पर RFID टैग लगाए जाते हैं और लोकोमोटिव में लगे रीडर के माध्यम से ट्रेन की सटीक लोकेशन, सिग्नल की स्थिति तथा गति सीमा की जानकारी प्राप्त होती है।

अहमदाबाद मंडल में 'कवच' प्रणाली का क्रियान्वयन

भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विकसित की गई उन्नत स्वदेशी प्रणाली 'कवच' का क्रियान्वयन अहमदाबाद मंडल में भी तीव्र गति से किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी तथा नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. वटवा लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति

वटवा लोको शेड में कुल 180 इंजनों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 72 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है, जो चरणबद्ध रूप से कवच की स्थापना का कार्य कर रही है।

2. साबरमती लोको शेड में कवच कार्य की प्रगति साबरमती लोको शेड में 34 इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है। इनमें से अब तक 6 इंजनों पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष इंजनों पर कार्य जारी है। इस कार्य हेतु तकनीकी कर्मचारी तैनात हैं, जो कवच की सूक्ष्म स्थापना प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

3. ट्रैक सेक्शनों पर कवच इंस्टालेशन की स्थिति

- अहमदाबाद–पालनपुर एवं अहमदाबाद–सामाख्याली सेक्शन (कुल 402 आरकेएम): इस रेलखंड पर 410.10 करोड़ रुपये की लागत से कवच इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है।
- पालनपुर–सामाख्याली–गांधीधाम सेक्शन (300 आरकेएम): इस खंड पर 182.81 करोड़ रुपये की लागत से कवच इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है।
- अहमदाबाद–गेरतपुर सेक्शन (13.42 किमी): इस सेक्शन पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है और यह खंड अब कवच से सुसज्जित हो गया है।
- अहमदाबाद डिविजन के सभी सेक्शनों में RFID टैग सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं तथा कवच-फिटेड लोको का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है।
- हाल ही में गांधीनगर कैपिटल और कलोल के बीच लगभग 20 किमी सेक्शन में सफल ट्रायल किया गया।
- ट्रायल के दौरान दो ट्रेनों को एक ही ट्रैक के एक ही ब्लॉक सेक्शन में चलाया गया। जैसे ही दोनों लोको लगभग 10 किमी की दूरी के भीतर आए, पीछे चल रहे लोको में स्वतः ब्रेक लग गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक ही ब्लॉक सेक्शन में दो ट्रेनों को आगे-पीछे नहीं चलाया जा सकता।
- किसी भी ट्रेन के एक ही ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करते ही स्वतः ब्रेक लग जाता है तथा चेतावनी स्वरूप हॉर्न भी बजने लगता है।
- जब दोनों लोको को आमने-सामने लाने का प्रयास किया गया, तब भी दोनों लोको में स्वतः ब्रेक लग गया, जिससे संभावित टक्कर टल गई।
- दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के घनी आबादी वाले मार्गों पर 1,452 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू हुआ।
- रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 8,570 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई, 1,100 टावर और 6,776 रूट किमी ट्रैकसाइड उपकरण स्थापित किए गए, तथा 767 स्टेशन डेटा सेंटर स्थापित किए गए.
- भारतीय रेलवे के सभी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन डायगोनल, हाई डेंसिटी नेटवर्क और चिन्हित खंडों को कवर करते हुए 24,427 रूट किमी ट्रैकसाइड कवच कार्यान्वयन कार्य शुरू किया गया है।
- भारतीय रेलवे की यह पहल न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ट्रेन संचालन को अधिक उत्तरदायी और नियंत्रित बनाती है। अहमदाबाद मंडल रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और 'कवच' प्रणाली इसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हो रही है।

क्रूड ऑयल वायदा में 215 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 543 रुपये और चांदी वायदा 262 रुपये बढ़ा

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 376064.28 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 25923.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 350140.55 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 38400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4305.33 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16012.51 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 156891 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157580 रुपये और नीचे में 155739 रुपये पर पहुंचकर, 155736 रुपये के पिछले बंद के सामने 543 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 156279 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 347 रुपये या 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ 127780 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 48 रुपये या 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 16029 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 156606 रुपये के भाव पर खूलकर, 157600 रुपये के दिन के उच्च और 155750 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 555 रुपये या 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ 156310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 157497 रुपये के भाव पर खूलकर, 158175 रुपये के दिन के उच्च और 156528 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 156546 रुपये के पिछले बंद के सामने 554 रुपये या 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 157100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 261457 रुपये के भाव पर खूलकर, 262899 रुपये के दिन के उच्च और 254412 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 256532 रुपये के पिछले बंद के सामने 262 रुपये या 0.1 फीसदी की बढ़त के साथ 256794 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 90 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 262374 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-

माइक्रो अप्रैल वायदा 115 रुपये या 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 262600 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। मेटल वर्ग में 2351.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 4.55 रुपये या 0.39 फीसदी गिरकर 1176.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 3.65 रुपये या 1.13 फीसदी लुढ़ककर 319.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.5 रुपये या 0.44 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 343.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 60 पैसे या 0.32 फीसदी के सुधार के साथ 187.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 25923.38 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 350140.55 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 16012.51 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38400 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 7480.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 8845 रुपये के भाव पर खूलकर, 9106 रुपये के दिन के उच्च और 8811 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 215 रुपये या 2.47 फीसदी की तेजी के संग 8935 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 213 रुपये या 2.44 फीसदी की बढ़त के साथ 8934 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 280.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 285.3 रुपये के दिन के उच्च और 279 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 279 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.4 रुपये या 1.94 फीसदी की बढ़त के साथ 284.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 5.4 रुपये या 1.94 फीसदी बढ़कर 284.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 999 रुपये के भाव पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी के सुधार के साथ 975.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8952.07 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7060.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1408.70 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 498.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.24 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 430.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 6094.79 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1360.43 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11182 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62830 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31994 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 465840 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65661 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7083 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19889 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 76646 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 28653 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31079 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 38370 पॉइंट पर खूलकर, 38400 के उच्च और 38365 के नीचले स्तर को छूकर, 127 पॉइंट बढ़कर 38400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10 रुपये की गिरावट के साथ 126 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.65 रुपये की बढ़त के साथ 14.05 रुपये हुआ।

सोना मार्च 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 77 रुपये की गिरावट के साथ 1040.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 270000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 684.5 रुपये की गिरावट के साथ 4821 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 44 पैसे की नरमी के साथ 8.75 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.82 रुपये की गिरावट के साथ 1.82 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 8900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 227.8 रुपये की गिरावट के साथ 124.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.85 रुपये की गिरावट के साथ 10.6 रुपये हुआ।

सोना मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 214 रुपये की गिरावट के साथ 662 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 124 रुपये की गिरावट के साथ 582.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.1 रुपये की बढ़त के साथ 7.54 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 4.3 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे द्वारा 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली 16 उपनगरीय सेवाओं का 15-डिब्बों में परिवर्तन

15-डिब्बों वाली सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर होगी 227

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वहन क्षमता बढ़ाने एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली मौजूदा 16 उपनगरीय सेवाओं को 15-डिब्बों वाली सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि कर बढ़ती यात्री संख्या को समुचित रूप से समायोजित करना है। इससे ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अतिरिक्त 15-डिब्बों वाली सेवाओं के शुरू होने के बाद उनकी कुल संख्या 211 से बढ़कर 227 हो जाएगी। हालांकि, उपनगरीय सेवाओं की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह 1414 ही रहेगी। बढ़ाई जा रही 16 सेवाओं में से 8 सेवाएं पीक आवर्स में (प्रातःकालीन पीक में 4 तथा सायंकालीन पीक में 4) परिचालित होंगी। यह पहल पश्चिम रेलवे की सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे मुंबई की जीवनरेखा और अधिक सुदृढ़ होगी। विस्तृत सूची परिशिष्ट–I में संलग्न है।

रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

जीएनएस)। वडोदरा मंडल द्वारा रेल अवसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आनंद–गोधरा खंड के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग संख्या 54ए पर रिलीविंग गर्डर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंफ्रा का यह महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 16 मार्च, 2026 को अप लाइन तथा 17 मार्च, 2026 को डाउन लाइन पर नियोजित 3 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया, जिससे यातायात संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। उक्त अवसंरचना कार्य के निष्पादन में 500 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक क्रेन का उपयोग किया गया, जिससे गर्डर लॉन्च अत्यंत सटीकता एवं सुरक्षित ढंग से किया जा सका। इस कार्य की समयबद्ध एवं सफल पूर्णता वडोदरा मंडल की तकनीकी दक्षता, सुनियोजित कार्यप्रणाली तथा प्रतिबद्धता का परिचायक है।

वडोदरा मंडल निरंतर रेल अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।

सूरत में अपराध और सशस्त्र डकैती पुलिस की नाकामियों के खिलाफ चेतावनी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शिकागो की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले छह महीनों से यहाँ लूटपाट, हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों द्वारा उत्पीड़न और खुलेआम दादागिरी आदि की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई और डराने-धमकाने का काम कहाँ है?

सूरत शहर में हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों द्वारा उत्पीड़न, लूटपाट, चोरी और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ विशेष पुलिस थानों में भी ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं। दिंडोली, लिंबायत, गोदादरा, पांदेसरा, सचिन, सचिन जीआईडीसी, उधना आदि थानों में गंभीर अपराध दर्ज किए जाते हैं। सामान्य अपराधों का निपटारा थानों से ही कर दिया गया। और पुलिस रिकॉर्ड में अधिक अपराध दर्ज न करके अपराधों की संख्या कम दिखाई जा रही है।

इस प्रकार, पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारियों को यह दिखाने के लिए झूठी छवि बनाते हैं कि उनके थाने में अपराध कम हुए हैं या अपराध दर घट गई है। जब हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली, सूदखोरों को परेशान करना, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल निरीक्षण के नाम पर अपराध स्थल पर ले जाया जाता है, तो पुलिस आरोपियों को लंगड़ाकर चलने की सलाह देती है ताकि वे तमाशा न करें और ऐसे अपराधियों को जनता के सामने प्रदर्शित न करें और यह न दिखाएं कि उन्होंने तृतीय श्रेणी की सजा अपनाई है। लेकिन उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उन्हें पुलिस का कोई डर या खौफ नहीं है। पुलिस केवल यह दिखाती है कि उन्होंने किसी बड़े अपराधी को पकड़ा है। जब कोई गंभीर अपराध होता है, तो आरोपी दो-तीन दिन तक छिप जाते हैं। और जैसे ही जनता का गुस्सा शांत होता है, आरोपी अपने (पुलिस) सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रकट होते हैं। या वे जगह दिखाते हैं ताकि पुलिस वहां जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर ले और जनता को यह दिखाए कि उन्होंने खुद उन्हें गिरफ्तार किया है। इस दौरान, यानी जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही होती है, तो आरोपियों को पुलिस पर हमला करते या हथियार से घायल करते हुए दिखाया जाता है, और पुलिस को आरोपियों के पैर में चोट पहुंचाते हुए दिखाया जाता है, यह कहते हुए कि उन्होंने पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की थी। असल में, यह सब सिर्फ एक नाटक है।

आजकल छात्र कलम और पेंसिल रखने के बजाय ऑनलाइन चाकू और चॉपस्टिक मंगवाते हैं। और वे सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम इनका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। पांदेसरा स्थित गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों के बीच हुई हालिया गैंगवार की घटना शिक्षा जगत, पुलिस और समाज के लिए शर्मनाक है। यदि छात्रों के माता-पिता या परिवार के पास लाइसेंसी हथियार हैं, तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसे हथियार छोटे बच्चों के हाथों में न पड़ें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का दक्षिण गुजरात के पर्यटन को सुपर बूस्ट : अब पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे सुदूरवर्ती जंगलों में

▸▸ दक्षिण गुजरात की खूबसूरत वादियों का सफर अब और भी सुगम और सुहाना होगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने की शानदार प्रगति, वर्ष 2024 में विदेश से आने वाले पर्यटकों में 14.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत के पर्यटन मानचित्र में गुजरात विशेष रूप से उभरकर सामने आया : वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में गुजरात देश भर में तीसरे स्थान पर

▸▸ मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट, पारसी टूरिज्म सर्किट, सूरत, तापी, डांग और नवसारी की इको-टूरिज्म साइट को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और अपग्रेड करने के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की

जीएनएस)। गांधीनगर : यदि आप अहमदाबाद, वडोदरा या सूरत जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और वीकेंड पर शहर के कोलाहल से दूर दक्षिण गुजरात में प्रकृति की गोद में तरोताजा होने के लिए प्राकृतिक जंगलों एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर घूमना चाहते हैं, तो अब आपको कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण गुजरात में स्थित पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और अपग्रेड करने के लिए सुपर बूस्ट दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूरत इकोनॉमिक रीजन (एसईआर) योजना (फेज-1) के अंतर्गत सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जैसे जिलों में अलग-अलग सड़कें बनाने और अपग्रेड करने के लिए 1185 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि आवंटित की है। इस योजना में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत जिलों में सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत किया जाएगा, आवश्यक जगहों पर फोर और सिक्स लेन सड़कें बनाई जाएंगी तथा कुछ शहरों में बाईपास सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। इससे दक्षिण गुजरात के पर्यटन स्थलों का सफर और भी सुगम एवं सुहाना हो जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने शानदार प्रगति की है। वर्ष 2024 में विदेश से आने वाले सैलानियों में 14.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत के पर्यटन मानचित्र में गुजरात विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में गुजरात देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है।

अब सुरत के सुवाली बीच का सफर होगा और भी आसान

सूरत के शांत और सुरम्य समुद्र तट यानी सुवाली बीच तक जाने वाले मोरा-सुवाली बीच रोड के विकास से सुवाली बीच तक जाना अब और भी आसान हो जाएगा। सुवाली बीच सूरत जिले के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यहां आयोजित होने वाला 'सुवाली बीच फेस्टिवल' अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। सड़क के विकास से पर्यटन गतिविधियों को अधिक बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी एक नई गति मिलेगी।

कोस्टल हाईवे फेज-1 के तहत सुवाली बीच रोड को 10.00 मीटर चौड़ा किया गया था। इसके बाद सुवाली बीच को सूरत जिले के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया। अब इस बीच के नजारों को देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। इसलिए, मोरा से सुवाली बीच रोड को फोरलेन किया जाएगा।

आसान होगा रजवाड़ी नगर धरमपुर का सफर

चिखली से खेरगाम होते हुए धरमपुर जाने वाली सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा, इससे धरमपुर जाना और भी आसान हो जाएगा। इस सड़क के चौड़ा होने से मानसून में प्रकृति की गोद में बसे धरमपुर और विल्सन हिल जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।

दक्षिण गुजरात प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से समृद्ध क्षेत्र है। यहां अनेक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान हैं, जो सुकून और शांति की अनुभूति कराते हैं। इनमें केवड़ी इको-टूरिज्म साइट (मांडवी), पदमडुंगरी इको-टूरिज्म साइट (डोलवण), उनाई मंदिर (वांसदा), वघई बॉटनिकल गार्डन, वांसदा नेशनल पार्क (वांसदा), पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और गिरा जलप्रपात जैसे अनेक स्थानों पर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहारने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए, इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को एक सुखद अनुभव देने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी से पर्यटन विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री ने दक्षिण गुजरात में पर्यटन स्थलों के अवसंरचना विकास के लिए यह बड़ी धनराशि आवंटित की है। सरकार के इन प्रयासों से पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र भी साकार होगा।

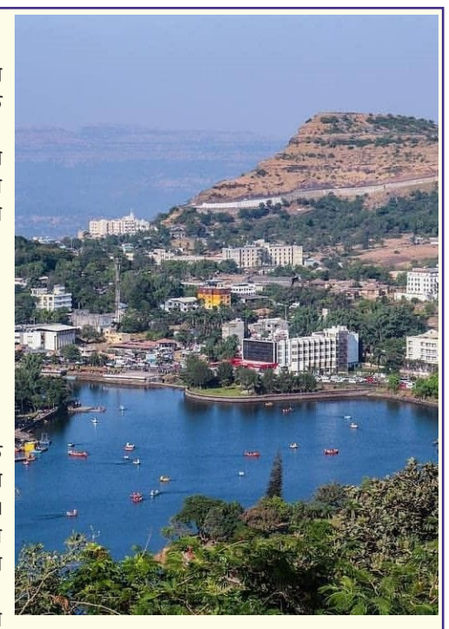

ऐतिहासिक अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट बनेगा नयनरम्य

महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा के रूट पर अब आसानी से यात्रा की जा सकेगी। यह सड़क अहमदाबाद-दांडी हेरिटेज रूट पर आने वाले कदरामा, एरथाण, टकरामा, भटगाम, मोहंमदपुरा, गोला और सांधियेर गांवों को जोड़ती है। इस सड़क को तीन मीटर से सात मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात का बोझ कम होने से इस ऐतिहासिक मार्ग का दौरा करना सुगम हो जाएगा।

कोस्टल हाईवे के जरिए संजाण और दमन अब और करीब हुए

वलसाड जिले में उमरसाडी से कोलक नदी कोस्टल हाईवे पर एक कॉज-वे बनेगा। यह कोस्टल हाईवे वलसाड और दमन को जोड़ने वाली एक अहम सड़क है। प्राकृतिक नजारों से भरपूर यह नयनरम्य सड़क दमण, उदवाड़ा अगियारी, उमरसाडी वॉक-वे ब्रिज आदि पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। मौजूदा 10 मीटर सड़क को अब चौड़ा करके फोरलेन बनाया जाएगा।

डांग का प्राकृतिक सौंदर्य अब शहरों से दूर नहीं

गुजरात का सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल डांग जिला अब दूर नहीं लगेगा। प्रकृति और संस्कृति के इस संगम स्थान की प्राकृतिक छटा को देखने के लिए कुछ ही देर में पहुंचा जा सकता है। डांग में वघई से आहवा जाने वाला राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) डांग जिले के अन्य गांवों को जिला मुख्यालय के साथ जोड़ता है। यह हाईवे पर्यटन एवं यात्राधाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सड़क शबरीधाम, पंपा सरोवर, अग्निकुंड और पांडव गुफा जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों और डॉन हिल स्टेशन, महाल कैंप साइट, देविनामाळ कैंप साइट, सापुतारा हिल स्टेशन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सड़क अब फोरलेन हो जाएगी, जिससे लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों तक जल्द पहुंच सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को राज्य में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने सूक्ष्म अध्ययन, जिलों की यात्रा तथा जनसंपर्क के बाद चर्चा-विचार के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी

जीएनएस)। गांधीनग : गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मंगलवार को गांधीनगर में अपनी विस्तृत तथा अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने सूक्ष्म अध्ययन कर, राज्य के जिलों की यात्रा कर, लोक अभिप्राय प्राप्त करके तथा व्यापक जनसंपर्क के बाद चर्चा-विचार के आधार पर तैयार की गई, जो राज्य सरकार को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस श्री सी. एल. मीणा, वरिष्ठ एडवोकेट श्री आर. सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती गीता श्रॉफ शामिल हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में विवाह, तलाक, विरासत में मिलने वाली संपत्ति और दत्तक जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचा समिति द्वारा सुझाव दिया गया है।

विशेष रूप से महिलाओं के समान अधिकारों और सुरक्षा को इस ड्राफ्ट में प्राथमिकता दी गई है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है।

गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट की तीन वॉल्यूम सौंपी। इस अवसर पर समिति के सलाहकार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, समिति के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, वैधानिक मामलों के सचिव श्री के. एम. लाला, कानून सचिव श्री उपेंद्र भट्ट तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पिंक टॉयलेट: गुजरात के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए गुजरात सरकार की नई पहल

▸▸ निर्मल गुजरात 2.0 के तहत राज्य के महानगर पालिका-नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी पवित्र यात्राधाम क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बनेंगे स्वच्छ और आधुनिक पिंक टॉयलेट

▸▸ वर्ष 2026-27 के राज्य के बजट में पिंक टॉयलेट के लिए 59.14 करोड़ का प्रावधान

▸▸ निर्मल गुजरात 2.0 पहल के तहत गुजरात को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रसर बनाने के लिए पिंक टॉयलेट के निर्माण सहित 4 नए घटकों का समावेश

जीएनएस)। गांधीनगर : वर्ष 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई निर्मल गुजरात योजना का दायरा आज बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, जो अब केवल स्वच्छता गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में निर्मल गुजरात 2.0 अभियान शुरू किया है और राज्य के शहरी इलाकों में नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने और गुजरात को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वच्छता से संबंधित निर्मल गुजरात 2.0 के तहत चार नए घटक शामिल किए गए हैं। इन चार घटकों में से एक है महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण। महिलाओं की सुविधा और स्वच्छता के लिए गुजरात के महानगर पालिका-नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी पवित्र यात्राधाम क्षेत्रों तथा तीर्थस्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा।

महिलाओं के लिए सुविधाजनक पिंक टॉयलेट की विशेषताएं

गुजरात सरकार ने हमेशा महिलाओं के लिए स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले पिंक टॉयलेट में कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि 4 नॉर्मल टॉयलेट सीट, दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 सीट, चेंजिंग रूम, बच्चों को दूध पिलाने के लिए रूम और महिला केयरटेकर क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। पिंक टॉयलेट के निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 के राज्य सरकार के बजट में 59.14 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में, जब पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तब पिंक टॉयलेट्स के निर्माण का यह निर्णय राज्य सरकार की महिलाओं के लिए स्वच्छता व सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

वर्ष 2026-27 में 'निर्मल गुजरात 2.0' अंतर्गत 4 नए घटकों का समावेश

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'निर्मल गुजरात 2.0' के तहत कुल 4 नए घटकों को शामिल किया गया है, जिनमें 1) स्वच्छ शहर – ठोस कूड़ा संग्रहण (डोर टु डोर कलेक्शन सुदृढ़ करना), 2) महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण, 3) पब्लिक टॉयलेट्स का संचालन और रखरखाव और 4) नदियों की सफाई शामिल है। इसके लिए इस वर्ष के राज्य के बजट में कुल 329.54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन नए घटकों के माध्यम से 100% डोर टु डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा और 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जाएगा।

नेशनल डिफेंस कॉलेज के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से की शिष्टाचार भेंट

▸▸ 'नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी' कार्यक्रम के तहत इकोनॉमिक सिक्योरिटी के स्टडी प्रोग्राम में 122 अधिकारी भाग ले रहे हैं

▸▸ गुजरात दौरे के दौरान 17 सदस्यीय दल ने गिफ्ट सिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर और जामनगर का दौरा किया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और कृषि विकास सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ एनडीसी के अधिकारियों ने गुजरात के समग्र आर्थिक विकास की गाथा जानने में दिखाई उत्सुकता

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मंगलवार को गांधीनगर में नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के स्टडी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्यों के दल ने शिष्टाचार मुलाकात की। नेशनल डिफेंस कॉलेज भारतीय सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों, सिविल सेवा के संयुक्त सचिवों और निदेशक स्तर के अधिकारियों तथा साझेदार देशों के विदेशी सैन्य अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अभ्यास पर पाठ्यक्रम चलाता है।

इस वर्ष इकोनॉमिक सिक्योरिटी विषय पर आधारित स्टडी कार्यक्रम की बैच में भारतीय सशस्त्र बलों को 61, सिविल सेवा के 20 और पार्टनर फॉरेन कंट्रीज के 41 सहित कुल 122 अधिकारी शामिल हैं।

इस स्टडी कार्यक्रम के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के अध्ययन दौरे के तहत गुजरात की यात्रा पर पहुंचे रियर एडमिरल श्री संदीप सिंह संधू के नेतृत्व में एनडीसी के 17 अधिकारियों के दल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दल में भारतीय सेना के तीनों अंगों के अलावा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), कम्युनिकेशन सर्विसेज तथा पार्टनर कंट्रीज के सैन्य अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस मुलाकात के दौरान एनडीसी के अधिकारियों ने गुजरात के समग्र आर्थिक विकास की गाथा के बारे में जानने में उत्सुकता दिखाई। विशेषकर, महिला सशक्तिकरण, संतुलित आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो रहे

विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ रोचक संवाद किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने नीति-संचालित राज्य (पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट) के रूप में ख्याति अर्जित की है और विकास का रोल मॉडल बना है। वाइब्रेंट समिट के जरिए गुजरात दुनिया भर के उद्योगों और निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रीन ग्रोथ और संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विस्तार से बताया कि सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से टूरिज्म को और वोकल फॉर लोकल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल कैनाल नेटवर्क के माध्यम से नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचाने से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की प्रत्येक योजना आम नागरिक को केंद्र में रखकर बनाई है। इतना ही नहीं, सैचुरेशन एप्रोच अपनाकर, जिनके लिए योजना बनी है, उन जरूरतमंद लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाकर 100 फीसदी सफलता का लक्ष्य भी उनके मार्गदर्शन में हासिल हो रहा है।

मुख्यमंत्री के साथ आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे एवं एसबीआई द्वारा दिवंगत रेल कर्मचारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान सौंपा गया

जीएनएस)। कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के एक वरिष्ठ मोटरमैन, जिनका ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मुंबई सेंट्रल मंडल में इस प्रकार का पहला बीमा भुगतान है, जो सितंबर 2025 में भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक के बीच उन्नत रेलवे सैलरी पैकेज (RSP) योजना के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत संभव हो पाया।

मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मेट्रो सर्कल की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती मंजू शर्मा ने 16 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल मंडल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी

को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर रेलवे एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुंबई सेंट्रल मंडल के कार्मिक विभाग ने सभी देयकों के समयबद्ध भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक्स-ग्रेशिया तथा अन्य पात्र मुआवजे शामिल हैं। यह बीमा राशि, रेलवे की नीति के अनुसार पहले से प्रदान किए गए अन्य सेटलमेंट लाभों के अतिरिक्त है।

आरएसपी योजना के अंतर्गत, एसबीआई में वेतन खाते रखने वाले रेल कर्मचारियों को व्यापक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जिसमें बिना किसी प्रीमियम या चिकित्सीय जांच के एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। दिवंगत वरिष्ठ मोटरमैन ने इस योजना का लाभ लिया था, जिससे उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

यह पहल भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।